District Level Workshop on Lokvani & eDS Held on 16th Nov. 2011
Organized By: District Administration & NIC, Gonda (UP)

District Administration in association with NIC, Gonda conducted One Day Workshop on Nov. 16, 2011. The workshop was chaired by Shri Janardan Baranwal, CDO Gonda. Shri Hemant Arora, DIO NIC, Gonda welcomed all the participants and explained the scope and objectives of the workshop.

The objectives of the workshop were to spread awareness on activities of Lokvani Society and delivery of citizen centric services to rural masses through Lokvani Kiosks. A total of 182 LOKVANI kiosks owners from all Nyaya Panchayats and town areas of district attended the workshop.

Shri Ajai Gopal Bhartariya, Technical Director, NIC-UP State Unit, Lucknow spoke on the importance and role of LOKVANI society to deliver the citizen centric services. Shri Shailesh Srivastava , PSA, NIC-UP State Unit, Lucknow explained the salient features and methodology of electronic delivery of various citizen services.

Other senior district officers took part and shared their views. All the participants appreciated the effort made by NIC and assured their active participation for implementation of the services at all levels.

ग्रामीणों की आवाज बनें लोकवाणी केन्द्र

सहारा 17-11

▶ लोकवाणी केन्द्र संचालकों की कार्यशाला

गोण्डा(एसएनबी)। शासन की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत जनसुविधाओं की इलेक्ट्रानिक डेलीवरी के लिए जिले में तैनात 182 लोकवाणी केन्द्र संचालक जिला प्रशासन के पार्टनर के रुप में अपील किया कि ये लोकवाणी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती लोगों की आवाज बनकर उभरें। इनका निर्धारित अवधि में निस्तारण करके इन्टरनेट पर अजय गोपाल ने बताया कि लोकवाणी केन्द्र पर शिकायतें/समस्याएं शासन स्तर पर भी परीक्षण की जायेंगी। सभी शिकायतों का प्रशासन दोनों इलेक्ट्रानिकली जनता के द्वार पर पहुंच रहा है। इससे लोगों के तहसील, ब्लाक, जिला मुख्यालय पर आवागमन तथा धन के अपव्यय से बचत होगी।

कार्यशाला का शुभारम्भ सी.डी.ओ. ने

प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित लोकवाणी संचालक व कार्यक्रम का उद्घाटन करते सी.डी.ओ। फोटो : एसएनबी

कार्य करेंगे। इस दृष्टिकोण से उनकी संवेदनशीलता तथा दायित्व अधिक हो जाता है।

उक्त बात मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन बरनवाल ने कही। वे जिला पंचायत सभागार में लोकवाणी केन्द्र संचालकों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया गया था। सी.डी.ओ. ने कहा कि संचालकों के इस कार्य में जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा।

अपर जिलाधिकारी विवेक पाण्डेय ने कहा कि जिले में 42 स्थानों के लिए रिक्तियां हैं। शीघ्र ही विज्ञापित करके इन स्थानों पर भी यह सेवा केन्द्र स्थापित कराया जायेगा। उन्होने जवाब उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने सभी संचालकों को सेवा करने की प्रतिज्ञा भी दिलायी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमन्त अरोरा ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि प्रथम चरण में शिकायतों/समस्याओं का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र जारी करने का काम इन केन्द्रों द्वारा किया जायेगा। इन प्रमाण पत्रों पर सम्बन्धित अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। सम्बन्धित केन्द्र संचालक प्रिन्ट आउट निकालकर देंगे तथा अपनी मुहर और हस्ताक्षर करेंगे। यह पेपर सभी सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों में वैध माना जायेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के टेक्निकल डाइरेक्टर (उ.प्र.) निस्तारण करके उसकी सूचना विभाग देगा जिससे शिकायतकर्ता को अवगत कराना होगा। प्रिन्ट आउट देने पर निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा। सभी शिकायतों की एक अलग संख्या होगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ.प्र. के प्रिन्सपल सिस्टम एनालिस्ट शैलेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक शिकायत कर्ता का मोबाइल नम्बर तथा फोटो दर्ज करना अनिवार्य है। आने वाले समय में इन केन्द्रों के माध्यम से और भी सुविधाएं जनमानस को उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए केन्द्र संचालक निर्धारित शुल्क ले सकेंगे।उन्होने कहा कि पहले प्रशासन समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता के द्वार जाता था। अब शासन और जिला दीप प्रज्वलित करके किया। एन.आई.सी. के अधिकारियों ने लैपटाप के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण के पूर्व दर्ज करने तथा उसे आवश्यक जानकारी देने का विधिवत प्रदर्शन करके बताया। प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट बी.बी. पाण्डेय ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सी.आर.ओ. उदयशंकर उपाध्याय, अमित कुमार मल्ल, डा. राजीव झा, आशुतोष सिंह, महेन्द्र सिंह, प्रभारी डी.डी.ओ. के.एन. पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, नगर पालिका/पंचायतों के अधिशासी अधिकारी गण, अपर मुख्य अधिकारी अशोक यादव, एन.आई.सी. से कमलेश सिंह, हृदयेश्वर राव, विनय उपाध्याय,आदि उपस्थित रहे।

प्रशासन के पार्टनर के रूप में काम करेंगे केंद्र

लोकवाणी केंद्र संचालकों की एक दिवसीय कार्यशाला में बताए गए नियम

अमर उजाला ब्यूरो

गोंडा। शासन की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत जन सुविधाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के लिए जिले में तैनात 182 लोकवाणी केन्द्र संचालक जिला प्रशासन के पार्टनर के रूप में कार्य करेंगे। इस दृष्टिकोण से उनकी संवेदनशीलता तथा दायित्व अधिक हो जाता है।

उक्त विचार मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन बरनवाल ने व्यक्त किया। वे बुधवार को जिला पंचायत सभागार में लोकवाणी केन्द्र संचालकों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया गया था। सीडीओ ने कहा कि संचालकों के इस कार्य में जिला प्रशासन हरसंभव सहयोग करेगा। अपर जिलाधिकारी विवेक पांडेय ने कहा कि जिले में 42 स्थानों के लिए रिक्तियां हैं। शीघ्र ही विज्ञापित करके इन स्थानों पर भी यह सेवा केन्द्र स्थापित कराया जायेगा। उन्होंने सभी संचालकों को सेवा करने की प्रतिज्ञा भी दिलायी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत अरोरा ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि प्रथम चरण में शिकायतों/ समस्याओं का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र जारी करने का काम इन केन्द्रों द्वारा किया जायेगा। इन प्रमाण पत्रों पर संबंधित

पंचायत सभागार में लोकवाणी के प्रशिक्षण में जानकारी देते अधिकारी।

अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। संबंधित केन्द्र संचालक प्रिंट आउट निकालकर देंगे तथा अपनी मुहर और हस्ताक्षर करेंगे। यह पेपर सभी सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों में वैध माना जायेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के टेक्निकल डाइरेक्टर उप्र. अजय गोपाल ने बताया कि लोकवाणी केन्द्रों पर शिकायतें/ समस्याएं शासन स्तर पर भी परीक्षण को जायेगी। सभी शिकायतों का निस्तारण करके उसकी सूचना विभाग को दी जाएंगी, इससे शिकायतकर्ता को अवगत कराना होगा। प्रिंट आउट देने पर निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उप्र. के प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट शैलेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर तथा फोटो दर्ज करना अनिवार्य है। आने वाले समय में इन केन्द्रों के माध्यम से और भी सुविधाएं जनमानस को उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए केन्द्र संचालक निर्धारित शुल्क ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले प्रशासन समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता के द्वारा जाता था। अब शासन और जिला प्रशासन दोनों जनता के द्वार पर पहुंच रहा है। इससे लोगों के तहसील, ब्लाक, जिला मुख्यालय पर आवागमन तथा धन के अपव्यय में बचत होगी। कार्यशाला का शुभारंभ सीडीओ ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट बीबी पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सीआरओ उदयशंकर उपाध्याय, अमित कुमार मल्ल, डॉ. राजीव झा, आशुतोष सिंह, महेन्द्र सिंह, प्रभारी डीडीओ केएन पांडेय, खंड विकास अधिकारी, नगर पालिका/ पंचायतों के अधिशाषी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी अशोक यादव, कमलेश सिंह, हृदयेश राव, विनय उपाध्याय, तूलिका श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

लोकवाणी केन्द्र संचालक प्रशासन के साथ करेंगे कार्य

संवाददाता । गोण्डा

शासन की 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की नीति के तहत जनसुविधाओं की इलेक्ट्रानिक डिलेवरी के लिए जिले में तैनात 182 लोकवाणी केन्द्र संचालक जिला प्रशासन के पार्टनर के रूप में कार्य करेंगे। इस दृष्टिकोण से उनकी संवेदनशीलता तथा दायित्व अधिक हो जाता है। उक्त विचार मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन बरनवाल ने व्यक्त किया। वे जिला पंचायत सभागार में आयोजित लोकवाणी केन्द्र संचालकों की एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। इसका आयोजन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया गया था। सीडीओ ने कहा कि संचालकों के इस कार्य में जिला प्रशासन हर सम्भव सहयोग करेगा। अपर जिलाधिकारी विवेक पाण्डेय ने कहा कि जिले में 42 स्थानों के लिए रिक्तियां हैं। शीघ्र ही, विज्ञापित करके इन स्थानों पर यह सेवा केन्द्र स्थापित कराया जायेगा। उन्होंने अपील किया कि ये लोकवाणी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती लोगों की आवाज बनकर उभरें, उनकी शिकायतों/समस्याओं को इण्टरनेट के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुँचाएं। इनका निर्धारित अवधि में निस्तारण करके इण्टरनेट पर जवाब उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने सभी संचालकों को सेवा करने की प्रतिज्ञा भी दिलाया।

जिला सूचना अधिकारी हेमन्त अरोरा ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि प्रथम चरण में शिकायतों/समस्याओं का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र जारी करने का काम इन केन्द्रों द्वारा किया जायेगा। इन प्रमाणपत्रों पर सम्बंधित अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। सम्बंधित केन्द्र संचालक प्रिन्ट आउट निकालकर देंगे तथा अपनी मुहर और हस्ताक्षर करेंगे। यह पेपर सभी सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों में वैध माना जायेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के टेक्निकल डाइरेक्टर (उप्र) अजय गोपाल ने बताया कि लोकवाणी केन्द्रों पर शिकायतें/समस्याएं शासन स्तर पर भी परीक्षण की जायेगी। सभी शिकायतों का निस्तारण करके उसकी सूचना विभाग देगा जिससे शिकायत कर्ता को अवगत कराना होगा। प्रिन्ट आउट देने पर निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा। सभी शिकायतों की एक अलग संख्या होगी।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उप्र के प्रिन्सिपल सिस्टम एनालिस्ट शैलेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक शिकायतकर्ता का मोबाइल नम्बर तथा फोटो दर्ज करना अनिवार्य है। आने वाले समय में केन्द्रों के माध्यम से और भी सुविधाएं जनमानस को उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए केन्द्र संचालक निर्धारित शुल्क ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले प्रशासन समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता के द्वार जाता था, अब शासन और जिला प्रशासन दोनों इलेक्ट्रानिकली जनता के द्वार पर पहुंच रहा है। इससे लोगों के तहसील, ब्लाक, जिला मुख्यालय पर आवागमन तथा धन के उपव्यय से बचत होगी। कार्यशाला का शुभारम्भ सीडीओ ने दीप प्रज्वलित करके किया। एनआईसी के अधिकारियों ने लैपटाप के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण के पूर्व दर्ज करने तथा उसे आवश्यक जानकारी देने का विधिवत प्रदर्शन करके बताया। प्रभारी नगर मजिस्टेट्र बी.बी.पाण्डेय ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सीआरओ उदयशंकर उपाध्याय, अमित कुमार साहू, डीडीओ के.एन.पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, नगर पालिका/पंचायतों के अधिशासी अधिकारीगण, अपर मुख्य अधिकारी अशोक यादव, एनआईसी के कमलेश सिंह आदि उपस्थित रहे।

जिले में तैनात हुए एक सौ बयासी लोकवाणी केन्द्र

अ/जा 1/7-11

गोण्डा (आ0 स0) शासन की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत जन सुविधाओ की इलेक्ट्रानिक डिलेवरी के लिए जिले मे तैनात 182 लोक वाणी केन्द्र संचालक जिला प्रशासन के परिवार के रुप मे कार्य करेंगे । इस दृष्टिकोण से उनकी संबेदन शीलता व दायित्व अधिक हो जाता है । उक्त विचार मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन बरनवाल ने ब्यक्त किया । वे जिला पंचायत सभागार मे लोक वाणी केन्द्र संचालको की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे । इसका आयोजन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया गया था । सीडीओ ने कहा कि संचालको के इस कार्य मे जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा । अपर जिलाधिकारी विवेक पाण्डेय ने कहा कि जिले मे 42 स्थानो के लिए रिक्तियां हैं शीघ्र ही विज्ञापित करके इन स्थानो पर भी यह सेवा केन्द्र स्थापित कराया जाएगा। उन्होने अपील किया कि यह लोक वाणी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती लोगो की आवाज बन कर उभरे उनकी शिकायतो व समस्याओ को इंटरनेट के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचाए। इनका निर्धारित अवधि मे निस्तारण करके इंटरनेट पर जवाब उपलब्ध कराया जाएगा । उन्होने सभी संचालको को सेवा करने की प्रतिज्ञा भी दिलाया । जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत अरोरा ने सभी का स्वागत किया । इस मौके पर सीआरओ उदय शंकर उपाध्याय,अमित कुमार मल्ल, डा0 राजीव झा , आशुतोष सिंह, डीडीओ के एन पाण्डेय आदि तमाम लोग मौजूद रहे

लोकवाणी केन्द्र संचालकों की कार्यशाला, शिकायतकर्ता, मोबाइल नं. व फोटो जरूर करें दर्ज

लोकवाणी संचालक प्रशासन के पार्टनर : सीडीओ

गोण्डा | हिन्दुस्तान संवाद

17-11

शासन की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत जनसुविधाओं की इलेक्ट्रानिक डेलीवरी के लिए जिले में तैनात 182 लोकवाणी केन्द्र संचालक जिला प्रशासन के पार्टनर के रूप में कार्य करेंगे। इस दृष्टिकोण से उनकी संवेदनशीलता तथा दायित्व अधिक हो जाता है। यह विचार मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन बरनवाल ने व्यक्त किया। वे जिला पंचायत सभागार में लोकवाणी केन्द्र संचालकों की एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। इसका आयोजन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया गया था। सीडीओ ने कहा कि संचालकों के इस कार्य में जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा।

अपर जिलाधिकारी विवेक पाण्डेय ने कहा कि जिले में 42 स्थानों के लिए रिक्तियां हैं। शीघ्र ही विज्ञापित करके इन स्थानों पर भी यह सेवा केन्द्र स्थापित कराया जाएगा। उन्होंने अपील किया कि ये लोकवाणी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती लोगों की आवाज बनकर उभरें, उनकी शिकायतों/समस्याओं को इण्टरनेट के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचाएं। इनका निर्धारित अवधि में निस्तारण करके इण्टरनेट पर जवाब उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी संचालकों को सेवा करने की प्रतिज्ञा भी दिलाया।

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत अरोरा ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि प्रथम चरण में शिकायतों/समस्याओं का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र जारी करने का काम इन केन्द्रों द्वारा किया जाएगा। इन प्रमाण पत्रों पर सम्बन्धित अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। सम्बन्धित केन्द्र संचालक प्रिंट आउट निकालकर देंगे तथा अपनी मुहर और हस्ताक्षर करेंगे। यह पेपर सभी सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों में वैध माना जाएगा।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के टकिनकल डायरेक्टर (उ.प्र.) अजय गोपाल ने बताया कि लोकवाणी केन्द्रों पर शिकायतें/समस्याएं शासन स्तर पर भी परीक्षण की जाएंगी। सभी शिकायतों का निस्तारण करके उसकी सूचना विभाग देगा जिससे शिकायतकर्ता को अवगत कराना होगा। प्रिंट आउट देने पर निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा। सभी शिकायतों की एक अलग संख्या होगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ.प्र. के प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट शैलेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक शिकायतकर्ता का मोबाइल नम्बर तथा फोटो दर्ज करना अनिवार्य है। आने वाले समय में इन केन्द्रों के माध्यम से और भी सुविधाएं जनमानस को उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए केन्द्र संचालक निर्धारित शुल्क ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि पहले प्रशासन समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता के द्वार जाता था, अब शासन और जिला प्रशासन दोनों इलेक्ट्रानिकली जनता के द्वार पर पहुंच रहा है। इससे लोगों के तहसील, ब्लॉक, जिला मुख्यालय पर आवागमन तथा धन के अपव्यय से बचत होगी।

कार्यशाला का शुभारम्भ सीडीओ ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। एनआईसी के अधिकारियों ने लैपटाप के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण के पूर्व दर्ज करने तथा उसे आवश्यक जानकारी देने का विधिवत प्रदर्शन करके बताया। प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट बीबी पाण्डेय ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सीआरओ उदयशंकर उपाध्याय, अमित कुमार मल्ल, डॉ. राजीव झा, आशुतोष सिंह, महेन्द्र सिंह, प्रभारी डीडीओ केएन पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, नगर पालिका/पंचायतों के अधिशासी अधिकारीगण, अपर मुख्य अधिकारी अशोक यादव, एनआईसी से कमलेश सिंह, हृदयेश्वर राव, विनय उपाध्याय, तूलिका श्रीवास्तव, कपिश्वर उपस्थित रहे।

जिला पंचायत सभागार में बैठक में मौजूद लोकवाणी केन्द्र संचालक • हिन्दुस्तान